साकाति. 574(अ)—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रत्यक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (शेयर पंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निर्देशित नियम बनाया है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का संधिनर्म नाम कंपनी (शेयर पंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रकट होगी।

2. कंपनी (शेयर पंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में, नियम 4 (जिसे इसमें इसके पथात मूल नियम कहा गया है) के उप नियम (1) में,

(i) खंड (ग) के स्थान पर निर्देशित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) अधिकार के विशिष्ट अधिकारों के लिए शेयरों के बारे में मताधिकार, किमी समय विशेष पर जारी विशिष्ट अधिकारों वाले इक्कापण शेयरों के संबंध में इसके मताधिकार सहित मानवताधिकार के चीहर प्रतिष्ठ निर्देश अधिक नहीं होगा;”;

(ii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा।

3. मूल नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के स्पष्टीकरण में, दोनों स्थानों पर आने वाले “निदेशक” शब्द के स्थान पर “निदेशक अथवा कंपनी सचिव” शब्द रखे जाएंगे।
4. मूल नियमों के नियम 12 के उपनियम (1) के परंपर के यथास्थिरण में —

(i) “आयोजित नीति और संबंधित विभाग द्वारा जारी तारीख 17 फरवरी, 2016 की स.क.मि. 180(ए)” अकरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर उद्धोग संबंधित और अलग आयोजित व्यापार विभाग द्वारा जारी तारीख 19 फरवरी, 2019 की स.क.मि. 127(ए),” अकर, अंक, शब्द और शब्द रखें जाएंगे।

(ii) “पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर “इस वर्ष” शब्द रखें जाएंगे।

5. मूल नियमों के नियम 18 के उप-नियम (7) के रूप में प्रशस्त उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्—

“(7) कंपनी 31 मार्च को समस्त होने वाले अन्य वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले दिवंगतों के संबंध में दिवंगत शोधन आर्थिकता (दिवंगत शोधन आर्थिकता) और निवेश या जमा राशि की अपेक्षा का अनुसार निष्क्रियता शरीर के अनुसार करेगी:—

(क) दिवंगत शोधन आर्थिकता का मूल, नामांकन के बुनाई के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभ में से किया जाएगा;

(ख) वार्तालाप, दिवंगत शोधन आर्थिकता और निवेश या जमा, की पर्याप्तता के निर्देश में सीमाएं निष्क्रियता होगी —

(i) मार्त्यसंकाल और निजी रूप में रखे गए दिवंगतों के लिए भारतीय रिजर्व बंक और बैंकारी कंपनियों द्वारा वित्तीय मंत्र अधिनियम या भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी दिवंगतों के लिए दिवंगत शोधन आर्थिकता अनुसार करेगी है;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (2) के खंड (72) के अर्थार्थवर्त्त अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए दिवंगत शोधन आर्थिकता, भारतीय रिजर्व बंक के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समान लागू होगी।

(iii) गृहीतक कंपनियों के लिए (उपकंड (i) में वार्तालापित अर्थव्यवस्था वित्तीय संस्थाओं और बैंकारी कंपनियों में श्याम), निष्क्रियता मामलों में दिवंगत शोधन आर्थिकता अनुसार करेगी है।

(अ) दिवंगतों के पतल्लु दंड के मामलों में —

क. भारतीय रिजर्व बंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-क के अर्थित भारतीय रिजर्व बंक में रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और राष्ट्रीय वास्तवीक बैंक में रजिस्ट्रीकृत आवासीय वित्तीय कंपनियों के लिए;

ख. अन्य गृहीतक कंपनियों के लिए;

(आ) निजी रूप में रखे गए दिवंगतों के मामलों में, उप-कंड के और ख में वित्तीय रूप से दिवंगत कंपनियों के लिए।

(ई) अन्य गृहीतक कंपनियों (उपकंड (i) में व्यापार-विनिर्देश अर्थव्यवस्था वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग कंपनियों से भिड़े) के लिए —

(उ) भारतीय रिजर्व बंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-स के अर्थित भारतीय रिजर्व बंक में रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए और राष्ट्रीय वास्तवीक बैंक में रजिस्ट्रीकृत आवासीय वित्तीय कंपनियों के लिए, निजी रूप से रखे गए दिवंगतों के मामलों में कोई दिवंगत शोधन आर्थिकता अनुसार करेगी है।

(आ) अन्य गृहीतक कंपनियों के लिए, दिवंगत शोधन आर्थिकता की पर्याप्तता, बाजार दिवंगतों के मूल्य का नियम प्रस्तावित किया गया।

(v) यदि कोई कंपनी बंड (व) के उप-बंड (iii) की मद (ए) अवधि मद (व) या बंड (व) के उपबंड (iv) की मद (व) में कवर की गई है, तो वह प्रत्येक वर्ष में अप्रैल के 30वें दिन अवधि इसमें पूर्ण बंड (व) के उपबंड (iii) की मद (ए) अवधि मद (व) या बंड (व) के उपबंड (iv) की मद (व) में नक्सल की गई कंपनी के लाभ चेक दिवंगतों के संबंध में, रक्षा उपबंड (v) में यह-व्यवस्थित किसी एक अवधि एक से अधिक राशियों में आमादी वर्ष के मार्च महाने 31वें दिन की समस्त हो रहे उस वर्ष के दौरान परिपक्व हो रहे अपने दिवंगतों का रक्षा का से कम पत्र प्रतिवर्ष याचिकातिस्वरूप अवधि नियम नियम करेगी।

परंतु यथास्थिति निवेदिता अवधि निवेदिता शेष रक्षा, उस वर्ष के मार्च महाने 31वें दिन की समस्त पर उस वर्ष के दौरान परिपक्व हो रहे हिंदी का रक्षा का से त्रिवृत पत्र प्रतिवर्ष में कम नहीं होगी।
(vi) उपबंध (v) के प्रयोजनार्थ, वयस्कता, नियोक्ति, निषेधायक अथवा निवेदियों की रीतियाँ निर्देशानुसार हैं:

(अ) किसी अनुसूचित बैंक में निषेधों में, भारत के किसी प्रधान मंत्री में मुक्त,

(ब) केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की भारतीय प्रतिष्ठानों में;

(च) भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 की धारा 20 के उप-खंड (k) में (च) और उप-खंड (ड) में वर्णित भारतीय प्रतिष्ठानों में;

(छ) भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 की धारा 20 के उप-खंड (च) के अधीन अनुसूचित किसी अन्य कंपनी द्वारा जारी भारतीय बैंड में:

परंतु व्यापारी सरकारी निवेदियों के मामले में, इन उपनियम के अनुसार निवेदियों द्वारा अपरिवर्तीय भारत के संवेदन में निवेदन आर्थिकता का सूचना किया जाएगा;

(ग) अधिक सरकारी संस्थाओं द्वारा निवेदियों के मामले में, इन उपनियम के अनुसार विविधता द्वारा अपरिवर्तीय भारत के संवेदन में निवेदन आर्थिकता का सूचना किया जाएगा;

(घ) विविधता आर्थिकता में जमा रकम कंपनी द्वारा विविधता विमोचन के प्रयोजन के सिवाय उपयोग में नहीं लाई जाएगी।

[फ. सं. 01/04/2013-सीएल. V-भाग-III]

के. पी. आर. भूमि, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिनियम संख्या सा.का.नि. 265(अ) द्वारा भारत के राज्यपाल, अमालारण, भाग II, खंड 3 के उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इसके प्रत्याय अधिनियम संख्या सा.का.नि. 434(अ) तारीख 7.5.2018 की अधिनियम का शासकीय किया गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2019

G.S.R. 574(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, in rule 4 (hereinafter referred to as the principal rules), in sub-rule (1), -

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) the voting power in respect of shares with differential rights of the company shall not exceed seventy two per cent. of total voting power including voting power in respect of equity shares with differential rights issued at any point of time;”;

(ii) clause (d) shall be omitted.

3. In the principal rules, in rule 5, in sub-rule (3), in the Explanation, occurring at both the places, for the word “director”, the words “director or company secretary” shall be substituted.

4. In the principal rules, in rule 12, in sub-rule (1), in proviso to Explanation, –

(i) for the letters, figures, brackets and words “G.S.R. 180(E), dated 17th February, 2016 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion” the letters, figures, brackets and words “G.S.R. 127(E), dated 19th February, 2019 issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade” shall be substituted.
(ii) for the words “five years”, the words “ten years” shall be substituted.

5. In the principal rules, in rule 18, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(7) The company shall comply with the requirements with regard to Debenture Redemption Reserve (DRR) and investment or deposit of sum in respect of debentures maturing during the year ending on the 31st day of March of next year, in accordance with the conditions given below:-

(a) Debenture Redemption Reserve shall be created out of profits of the company available for payment of dividend;

(b) the limits with respect to adequacy of Debenture Redemption Reserve and investment or deposits, as the case may be, shall be as under:-

(i) Debenture Redemption Reserve is not required for debentures issued by All India Financial Institutions regulated by Reserve Bank of India and Banking Companies for both public as well as privately placed debentures;

(ii) For other Financial Institutions within the meaning of clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013, Debenture Redemption Reserve shall be as applicable to Non–Banking Finance Companies registered with Reserve Bank of India.

(iii) For listed companies (other than All India Financial Institutions and Banking Companies as specified in sub-clause (i)), Debenture Redemption Reserve is not required in the following cases -

(A) in case of public issue of debentures –
   A. for NBFCs registered with Reserve Bank of India under section 45-IA of the RBI Act, 1934 and for Housing Finance Companies registered with National Housing Bank;
   B. for other listed companies;

(B) in case of privately placed debentures, for companies specified in sub-items A and B.

(iv) for unlisted companies, (other than All India Financial Institutions and Banking Companies as specified in sub-clause (i)) -

(A) for NBFCs registered with RBI under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and for Housing Finance Companies registered with National Housing Bank, Debenture Redemption Reserve is not required in case of privately placed debentures.

(B) for other unlisted companies, the adequacy of Debenture Redemption Reserve shall be ten percent. of the value of the outstanding debentures;

(v) In case a company is covered in item (A) or item (B) of sub-clause (iii) of clause (b) or item (B) of sub-clause (iv) of clause (b), it shall on or before the 30th day of April in each year, in respect of debentures issued by a company covered in item (A) or item (B) of sub-clause (iii) of clause (b) or item (B) of sub-clause (iv) of clause (b), invest or deposit, as the case may be, a sum which shall not be less than fifteen per cent., of the amount of its debentures maturing during the year, ending on the 31st day of March of the next year in any one or more methods of investments or deposits as provided in sub-clause (vi):

Provided that the amount remaining invested or deposited, as the case may be, shall not at any time fall below fifteen percent. of the amount of the debentures maturing during the year ending on 31st day of March of that year.

(vi) for the purpose of sub-clause (v), the methods of deposits or investments, as the case may be, are as follows:—

(A) in deposits with any scheduled bank, free from any charge or lien;

(B) in unencumbered securities of the Central Government or any State Government;

(C) in unencumbered securities mentioned in sub-clause (a) to (d) and (ee) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882;

(D) in unencumbered bonds issued by any other company which is notified under sub-clause (f) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882:
Provided that the amount invested or deposited as above shall not be used for any purpose other than for redemption of debentures maturing during the year referred above.

(c) in case of partly convertible debentures, Debenture Redemption Reserve shall be created in respect of non-convertible portion of debenture issue in accordance with this sub-rule.

(d) the amount credited to Debenture Redemption Reserve shall not be utilized by the company except for the purpose of redemption of debentures."

[F. No. 01/04/2013-CL-V- Part-III]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 265(E), dated 31st March, 2014 and which was last amended vide Notification No. GSR 434(E) dated 7.05.2018.